added advantage to the Indian exporters and to earn the foreign exchange to our country. Hence, the hon. Chairman is requested for compassionate and urgent intervention to resolve the delisting matter for restoring delisted shrimp export companies to export shrimp consignments to European Union countries, UK and Russia for enhancing the market opportunities, strengthening the industry's global reach and supporting the sustainable growth of Indian Seafood exports with key focus on shrimp. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Masthan Rao Yadav Beedha: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal) and Shri A.A. Rahim (Kerala).

Now, Shri Satnam Singh Sandhu on 'Concern over Increasing Cases of Grabbing of NRIs' Properties in our Country'; not present. Shri Sanjay Singh on 'Concern over Social and Economic Conditions of Sick Workers of Coal India'.

Concern over social and economic conditions of sick workers of Coal India

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही गम्भीर विषय पर अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मान्यवर, देश भर में बिजली की आपूर्ति जिस थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से होती है, उसको संचालित करने में कोल इंडिया का और कोल इंडिया के मज़दूरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। महोदय, मुझे याद है कि जब कोरोना का समय था, उस वक्त भी कोल इंडिया ने अपना प्रोडक्शन बंद नहीं किया था और मज़दूरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर देश के अंदर बिजली की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए काम किया।

मान्यवर, कोल इंडिया का खुद का national Wages Act है, उस national Wages Act के तहत यह साफ तौर पर लिखा गया है, उसका क्लॉज़ 9.4 कहता है कि जो मज़दूर कोल इंडिया में काम करते-करते गम्भीर रूप से बीमार हो जाएगा, जैसे किसी को कैंसर की बीमारी, लीवर या किडनी की गम्भीर बीमारी हो गई, तो उसके लिए यह नियम बनाया गया कि उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी और इन गम्भीर बीमारियों के लिए चिकित्सकीय परीक्षण कोल इंडिया का मेडिकल बोर्ड करेगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 18 नवम्बर, 2017 - करीब सात साल से अधिक का समय हो गया है, आज तक वह मेडिकल बोर्ड काम ही नहीं कर रहा है। वे जो मज़दूर हैं, उन्होंने कई बार महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रार्थना पत्र लिखा, कई बार आदरणीय प्रधान मंत्री जी को प्रार्थना पत्र लिखा और कई बार कोयला मंत्री जी को प्रार्थना पत्र लिखा, उसके बाद वहां से जो रिप्लाई आया, वह भी संतोषजनक नहीं है, वह रिप्लाई भी उनके पास था।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आपने उनके लिए Wages Act बना रखे हैं और यह नियम है कि जो लोग गम्भीर रूप से बीमार होंगे,

मेडिकल बोर्ड उनका चेकअप करेगा और उनके dependents को नौकरी दी जाएगी, तो उस मेडिकल बोर्ड को 7 साल से क्यों बंद रखा गया है, वह क्यों काम नहीं कर रहा है? पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग कर चुके हैं, वे इस परिस्थिति में मरना चाहते हैं, उन लोगों की तकलीफों पर ध्यान दिया जाए और मेडिकल जांच कराकर उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाए, कोल इंडिया में नौकरी प्रदान की जाए, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Sanjay Singh: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Ritabrata Banerjee (West Bengal), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Saket Gokhale (West Bengal), and Shrimati Renuka Chowdhury (Telangana).

Demand to include Lepcha, Bhutia and Limbu Language in the Eighth Schedule of the Constitution of India

SHRI DORJEE TSHERING LEPCHA (Sikkim): The Government of Sikkim, since its merger with the Union of India, has taken a bold step towards promotion of languages in the State. It is to place on record that the first democratically elected State Government had passed a historic Sikkim Official Languages Act, 1977 on 25th October 1977 and adopted Nepali, Bhutia and Lepcha Languages as the State Official Languages of Sikkim and, thereafter, Limbu language was also adopted as the Official State Language of Sikkim through the Sikkim Official Languages (Amendment) Act, 1981. Moreover, with the introduction of Lepcha, Bhutia and Limbu languages in the school curriculum in the State, this language has been further extended to the Post-Graduate courses and presently further extended to Ph.D. under Sikkim Central University. News bulletin in All India Radio, Gangtok, are being aired in these three languages. Similarly, Sikkim Herald, a weekly newsletter, is also being published in these languages edition through Information and Public Relations Department, Government of Sikkim. In addition, the Sikkim Legislative Assembly had also adopted the Resolution in the year 2008 for inclusion of Lepcha, Bhutia and Limbu languages in the Eighth Schedule of the Constitution of India.